



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 1993/श्रावण 27, 1915

No. 492] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 1993/SRAVANA 27, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1993

अधिसूचना संख्या 10/(ग्रा. ई)/92-97

का.ग्रा. 621 (अ) :—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सां.ग्रा. 222 (अ) दिनांक 31 मार्च, 1993 के अन्तर्गत प्रकाशित निर्यात-आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

अध्याय 12 में मौजूदा पैराग्राफ 140 के बाद निम्नलिखित नया पैरा 140-क जोड़ा जाएगा :—

“राज्य निगम 140-क. उपर्युक्त में अन्य किसी बात का उल्लेख होते हुए भी संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा नामांकित एक राज्य निगम को एक निर्यात सदन के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है भले ही पैराग्राफ 138, 139 और 140 के साथ पठित पैराग्राफ 137 में यथा निर्धारित मान्यता प्रदान करने के मानदण्ड की पूर्ति न होती हो। इसका लाभ इस संबंध में अधिसूचित किए जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार केवल एक बार ही उपलब्ध होगा। इस प्रकार से मंजूर किए गए दर्जे की प्राथमिक वैधता के बाद नए सिरे से मान्यता देने पर केवल तभी विचार किया जाएगा जबकि ऐसा दर्जा देने के लिए निर्धारित सामान्य मानदण्ड के संबंध में संतुष्टि हो जाए।”

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. 6/57/93-ग्राईपीसी-2 से जारी]

अजीत कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार
और अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th August, 1993

NOTIFICATION NO. 10(RE)/92-97

S.O. 621(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised Edition : March, 1993) Published under the Notification of Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 222(E) dated the 31st March, 1993 :

In Chapter XII, the following new paragraph 140A shall be added after the existing paragraph 140 :—

“State Corporation

140A. Notwithstanding anything mentioned above, one State Corporation nominated by the respective State Governments|Union Territories may be recognised as an Export House only, even though

the criterion for recognition, as laid down in paragraph 137 read with paragraphs 138, 139 and 140 above, is not fulfilled. This benefit shall be available only once in accordance with the procedure to be notified in this behalf. After the expiry of the initial validity period of the status so granted, fresh recognition shall be considered, only if it satisfies the normal criterion laid down for grant of such status”

2. This issues in public interest.

[Issued from File No. 6/57/93-IPC-II]

AJIT KUMAR, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

